जनसत्ता

सेना की चिंता

सेना को बेहद घटिया किस्म का गोला-बारूद मिलने की जो शिकायतें सामने आई हैं, वे चौंकाने वाली हैं। इससे इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि मोर्चे पर हमारे जवानों को कैसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता होगा। यह गोला-बारूद अगर निजी कंपनियों में बन रहा होता या किसी दूसरे देश से खरीदा गया होता तो एकबारगी लगता कि इसमें गड़बड़ी हो रही होगी और मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसा खेल चल रहा होगा। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि खराब गुणवत्ता वाला गोला-बारूद हमारी ही सरकारी फैक्ट्रियों में बन रहा है। सेना के लिए छोटे हथियार, उपकरण और गोला-बारूद ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) के तहत चलने वाले कारखाने बनाते हैं। ओएफबी रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आता है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब पिछले कुछ सालों में इसकी वजह से टैंकों और बंदूकों में विस्फोट की कई घटनाएं सामने आईं। अपने ही जवानों को घटिया गोला-बारूद देकर हम देश की सुरक्षा से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, जवानों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं।

सवाल है कि आखिर रक्षा मंत्रालय की फैक्ट्रियों में घटिया गुणवत्ता वाला सामान कैसे बन रहा है, खासतौर से गोला-बारूद, जिसका इस्तेमाल दुश्मन से मोर्चा लेते वक्त किया जाना हो। सेना में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण, वाहन, हथियार आदि सरकार के तहत ही चलने वाली फैक्ट्रियों में इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न हो सके। इनके लिए बजट भी भरपूर होता है। फिर भी अगर कोई सामान घटिया गुणवत्ता वाला बन रहा है तो यह गंभीर बात है। यह सीधे-सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इससे तो यही आभास होता है कि हमारे आयुध कारखाने भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि गोला-बारूद तक में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। भारतीय सेना को गोला बारूद की आपूर्ति सेना के गुणवत्ता नियंत्रण महानिदेशालय से गहन जांच के बाद की जाती है। गोला-बारूद बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी पदार्थों की अधिकृत प्रयोगशालाओं में जांच की जाती है। सेना को दिए जाने से पहले इनके विशेष परीक्षण भी किए जाते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण की इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद भी अगर घटिया सामान सेना को मिलता है, तो निश्चित ही यह गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए।

सेना ने रक्षा मंत्रालय को बताया है कि खराब गोला-बारूद से टी-72, टी-90 और अर्जुन टैंक और बंदूकों में किस तरह से हादसे होते रहे हैं। इस तरह की बढ़ती घटनाओं की कीमत सेना को अपने अधिकारियों और जवानों की जान के रूप में चुकानी पड़ती है। सैनिकों के लिए गोला-बारूद ही एक तरह से पहला हथियार होते हैं। मोर्चे पर टैंकों और बंदूकों में गोला-बारूद ही इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर जवानों को देश की ही फैक्ट्रियों में बना खराब सामान मिलेगा तो मोर्चे पर कैसे टिक पाएंगे, यह किसी ने नहीं सोचा। यह देश के सैन्य साजोसामान बनाने वाले प्रतिष्ठानों की साख पर प्रश्नचिह्न है। गुणवत्ता के प्रति ऐसी गंभीर लापरवाही कहीं न कहीं संदेह तो पैदा करती है। ओएफबी ने तो इससे पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि हम बढ़िया गुणवत्ता वाला गोला-बारूद सेना को देते हैं, लेकिन वह इसका रखरखाव कैसे करती है, यह उसे देखना है। लेकिन सेना ने इस मामले को जितनी गंभीरता से लिया है, वह हमारे आयुध कारखानों को संचालित करने वाले तंत्र को कठघरे में खड़ा करता है। भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए सरकार को इस मामले में तत्काल कदम उठाना चाहिए।

सुरक्षा का सफर

सड़क पर दुपहिया वाहन चलाने वाले ऐसे तमाम लोग दिख जाते हैं जो हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझते। ऐसे लोगों को न सिर्फ इस बात की फिक्र नहीं ही होती कि वे गैरकानूनी तरीके से वाहन चला कर कोई अपराध कर रहे हैं, बल्कि यह भी याद रखना जरूरी नहीं लगता कि इस तरह की लापरवाही बरत कर वे अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। देश भर में अलग-अलग राज्यों में लोगों की इस आदत पर लगाम के लिए अभियान चलाए जाते हैं, कानूनन जुर्माना भी लगाया जाता है, मगर यह समझना मुश्किल है कि अपनी ही सुरक्षा को लेकर ऐसी लापरवाही के पीछे किस तरह का शौक है जो सुरक्षित सफर और हादसे की स्थिति में जिंदा बचने की जरूरत पर हावी हो जाता है। एक ताजा पहलकदमी के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक जून से वैसे दुपहिया वाहन के चालकों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा। यह नियम समूचे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लागू होगा। जाहिर है, यह किसी राज्य के एक खास इलाके के प्रशासन की ओर से की गई पहल है, जिसमें बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चलाने वालों को संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि अगर वे अपनी जान और हिफाजत को लेकर सावधानी नहीं बरतेंगे तो उसके बदले उन्हें न सिर्फ जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि पेट्रोल नहीं मिलने जैसी असुविधा भी उठानी पड़ सकती है।

यह एक जगजाहिर तथ्य है कि सड़क हादसों में दुपहिया चलाने वाले जितने लोगों की जान गई है, उनमें से ज्यादातर की जान सिर्फ हेलमेट पहनना सुनिश्चित करके बचाई जा सकती थी। आए दिन होने वाले हादसों में कई लोग अपने सामने देखते हैं कि हेलमेट नहीं होने की वजह से ही पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। इसके बावजूद लोग महज अपने आराम या शौक के लिए तो कभी धार्मिक पहचान के नाम पर हेलमेट पहनने से बचने या इनकार करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के सवाल पर काफी जद्दोजहद देखी गई थी। जबकि दुपहिया वाहन के हादसे की स्थिति में चोट किसी को भी बराबर ही लगेगी। आज भी सड़कों पर ऐसे दृश्य आम हैं जिनमें दुपहिया चालक और उस पर बैठे लोग बिना हेलमेट के होते हैं। कई लोग अपने दुपहिया वाहन में हेलमेट लटका कर रखते हैं और यातायात पुलिस के जुर्माने से बचने के लिए कभी-कभार लगा लेते हैं।

हेलमेट पहन कर वाहन चलाना कोई ऐसा काम नहीं है, जिससे किसी तरह की असुविधा होती हो। लेकिन कई बार लोग अपने हेलमेट को पहनना जरूरी नहीं समझते और इस बात को लेकर बेफिक्र रहते हैं कि कुछ नहीं होगा। सच यह है कि हादसे अचानक ही होते हैं, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। मामूली-सी कोताही की वजह से चालक हादसे की चपेट में आ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उसके सिर पर हेलमेट होता है तो गंभीर चोट लगने की गुंजाइश कम हो जाती है। कायदे से होना यह चाहिए कि दुपहिया चलाने और उस पर पीछे बैठ कर सफर करने वालों को खुद ही अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक होना चाहिए और हर हाल में हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट चालक की ही सुरक्षा के लिए है, जिसके लिए सरकार को कानून बना कर लागू करना पड़ा। लेकिन क्या यह किसी व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वह अपने साथ-साथ वाहन पर बैठे अन्य साथी के सुरक्षित सफर को लेकर सजग रहे?

कल्पमेधा

सब धोखों में पहला और सबसे खराब है, अपने को धोखा देना।
-वेली

हितों के लिए बदलती कूटनीति

संजीव पांडेय

पाकिस्तान को लगता है कि ज्यादा संबंध खराब होने की स्थिति में चाहबहार से भारत को ईरान बाहर करेगा और इसका सीधा लाभ चीन और पाकिस्तान को मिलेगा। चीन ने हाल ही में आरोप भी लगाया कि भारत चीन द्वारा विदेशों में विकसित किए जा रहे बंदरगाहों के विकास में अड़ंगा लगा रहा है। चीन ने विशेष तौर पर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का नाम लिया था और कहा था कि भारत इसके विकास में रोड़ा अटका रहा है।

मसला सिर्फ चीन-अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का नहीं है। मामला एशियाई कूटनीति में सर्वोच्चता हासिल करने का भी है। भारत ने ईरान से तेल आयात पूरी तरह रोकने का फैसला किया है। वहीं ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तेहरान पहुंचे और ईरान से आर्थिक सहयोग बढ़ाने व क्षेत्रीय सहयोग के लिए साथ में काम करने का वादा किया। हालांकि ईरान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इमरान खान का ईरान दौरा कई मायनों में महत्त्वपूर्ण था क्योंकि इमरान के लक्ष्य में भारत-ईरान संबंध भी हैं। इमरान ने ईरान के साथ आर्थिक साझेदारी को लेकर बातचीत की, आतंकवाद रोकने पर बातचीत की। दोनों मुल्कों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की बातचीत हुई, ईरान से खरीदी जाने वाली बिजली को लेकर बात हुई। वहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बीच क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। जब भारत अमेरिकी दबाव में ईरानी तेल के आयात से पीछे हट रहा है, तब पाकिस्तान ईरानी तेल और गैस आयात पर विचार कर रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान किस हद तक ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को मानेगा।

पिछले दिनों अमेरिका ने आतंकी मसूद अजहर के बहाने भारत-ईरान संबंधों को लेकर खुली राय रखी थी। मसूद को लेकर अमेरिका ने भारत को जो खुला समर्थन दिया, उसके बदले वह चाहता था कि भारत ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे। वैसे बीते दिनों मसूद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाई गई पाबंदी को भारत की कूटनीतिक जीत बताया गया था, क्योंकि इस बार चीन ने विरोध नहीं किया। पाकिस्तान भी चुप था। पाकिस्तान को इतना पता था कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगने से जमीन पर कुछ खास परिवर्तन नहीं आने वाला। 'वन बेल्ट-वन रोड' पर चीन में हुई बैठक से ठीक पहले भारतीय विदेश सचिव चीन गए थे। इसी दौरान इमरान खान बेल्ट एंड रोड फोरम की बैठक में भाग लेने चीन पहुंचे थे। उनकी चीनी अधिकारियों से बातचीत हुई। इसके बाद मसूद अजहर पर चीन ने रणनीति बदली। हालांकि भारत ने भी इसके लिए प्रयास कम नहीं किए थे। लेकिन इसके एवज में पश्चिमी देशों ने भारत को कूटनीतिक समर्थन मुफ्त में नहीं दिया, यह भी सच्चाई है।

दूसरी तरफ चीन को यह डर था कि मसूद अजहर पर ज्यादा अड़ने से चीन की वैश्विक छवि खराब होगी। इस बार पाकिस्तान ने भी व्यावहारिक रणनीति अपनाई, क्योंकि उसे अपनी खराब होती आर्थिक स्थिति की खासी चिंता है। पाकिस्तान यह अच्छी तरह जानता है कि अजहर पर प्रतिबंध कागजों में ही लगेगा, जमीनी कार्रवाई तो उसे ही करनी है। आतंकी गुटों पर कार्रवाई के मामले में पाकिस्तान अभी तक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है, चाहे अमेरिका विरोधी आतंकी गुट हक्कानी नेटवर्क हो या आतंकी हाफिज सईद का संगठन।

मसूद अजहर पर भारत की जीत सिर्फ मनोवैज्ञानिक जीत है। वैश्विक आतंकी घोषित होने से अजहर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान मसूद अजहर पर सख्त कार्रवाई करने से बचेगा, वह अजहर के मदरसों, खातों और संपत्तियों पर केवल दिखावे की कार्रवाई करेगा। दरअसल, भारत ने मसूद अजहर को तो वैश्विक आतंकी घोषित करवा दिया, लेकिन दूसरी सच्चाई यह है कि मसूद का संगठन जैश-ए-मोहम्मद कई साल पहले वैश्विक आतंकी सूची में डाला जा चुका है। जैश और इससे जुड़े दो बड़े ट्रस्ट अल रशीद ट्रस्ट और अल अख्तर ट्रस्ट पर 2003 और 2005 में प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद जैश की आतंकी गतिविधियों पर पाकिस्तान ने कोई रोक नहीं लगाई। सच्चाई तो यही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 का असर दुनिया के आतंकी संगठनों पर नहीं है। आतंकी संगठनों की संपति, पैसे आदि कागजों में जब्त किए जाते हैं।

जब्ती से पहले आतंकी संगठन पैसे और संपत्ति अपने दूसरे ट्रस्टों को हस्तांतरित कर देते हैं। हाफिज सईद भी वैश्विक आतंकी सूची में काफी पहले आ गया था। लेकिन उसकी गतिविधियां आज भी जारी हैं, उसके संगठन को हथियारों की आपूर्ति आज भी हो रही है। हाफिज कई दूसरे ट्रस्टों के माध्यम से अपने काम कर रहा है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 में शामिल होने के बाद भी हाफिज पाकिस्तान में खुला घूमता

है, उसने मिल्ली मुसलिम लीग नामक राजनीतिक दल भी बना लिया है, खुलेआम भारत विरोधी जलसा करता है। आजतक उसका कुछ नहीं बिगड़ा।

पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में व्यावहारिक रणनीति पर चलते हुए अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश की है। हाल में इमरान खान ने साफ कहा कि क्षेत्रीय शांति को लेकर पाकिस्तान तत्पर है, पर यह तभी संभव है जब भारत-पाकिस्तान संबंध ठीक होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी उससे बातचीत शुरू हो जाएगी और संबंध भी सुधरेंगे। इमरान ने ऐसे बयान पाकिस्तानी सेना की सहमति से ही दिए हैं।

भारत चीन की ओबीओआर परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है। चीन किसी भी कीमत पर भारत के विरोध को ठंडा करना चाहता है, क्योंकि भारत के विरोध का असर छोटे एशियाई मुल्कों पर पड़ता है। श्रीलंका और मलेशिया जैसे देशों में चीन की कुछ परियोजनाओं का विरोध हुआ। चीन इसके पीछे भारत के रवैये को देखता है। तभी से चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत बेल्ट एंड रोड के प्रति आक्रामक रवैया न अपनाए।

पाकिस्तान को पता है कि अमेरिकी दबाव में भारत ईरानी तेल के आयात को पूरी तरह रोकेगा। पाकिस्तान इसका लाभ उठाना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी ही भारत-ईरान के अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान को हमेशा यही डर रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां ईरान की सीमा में सक्रिय हैं। चाहबहार में भारत की मौजूदगी से पाकिस्तान को भारी नुकसान है, क्योंकि चाहबहार परियोजना पूरी हो जाने के बाद अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। अभी अफगानिस्तान अपनी जरूरी चीजों का आयात चाहबहार के रास्ते कर रहा है। भारत भी अफगानिस्तान में अपना सारा निर्यात चाहबहार के रास्ते ही कर रहा है। पाकिस्तान को यह लगता है कि ईरान से तेल खरीद बंद होने के बाद भारत-ईरान संबंधों में तनाव आएगा। यह पहली बार हो रहा है कि जब भारत ने ईरान से पूरी तरह से तेल आयात को रोका है। पिछली बार जब अमेरिकी प्रतिबंध लगा था तो भारत ने पूरी तरह से ईरानी तेल आयात को नहीं रोका था।

पाकिस्तान को लगता है कि ज्यादा संबंध खराब होने की स्थिति में चाहबहार से भारत को ईरान बाहर करेगा और इसका सीधा लाभ चीन और पाकिस्तान को मिलेगा। चीन ने हाल ही में आरोप भी लगाया कि भारत चीन द्वारा विदेशों में विकसित किए जा रहे बंदरगाहों के विकास में अड़ंगा लगा रहा है। चीन ने विशेष तौर पर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का नाम लिया था और कहा था कि भारत इसके विकास में रोड़ा अटका रहा है। दरअसल, ग्वादर के विकास में मुख्य रोड़ा ही चाहबहार है जहां भारत का निवेश है। पाकिस्तान ईरान से संबंधों को इसलिए भी नए सिरे से निर्धारित करना चाहता है कि अफगानिस्तान में ईरान की खासी भूमिका है। अफगान शांति वार्ता में भी ईरान की भागीदारी है। पाकिस्तान-अफगान सीमा पर लगातार तनाव से पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान हो रहा है। चमन और तोरखम सीमा पूरी तरह से व्यापार के लिहाज लाभदायक है, लेकिन इसका लाभ पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान को ऊर्जा की भारी जरूरत है।

जीवन की राह

साकेत सहाय

जिंदगी जिंदादिली का दूसरा नाम है। जब तक जियो, मस्ती से जियो! अगर आपके साथ किसी का तनाव है तो आज ही उसे सुलझा लीजिए। माफी मांगना और माफ करना, ये समझदार लोगों के काम हैं। उस पर दिन-रात सोचना, अपना नुकसान करना नासमझ लोगों का काम है। हम सभी ने एक कहानी जरूर सुनी होगी। दो बौद्ध भिक्षु कहीं जा रहे थे। उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था कि स्त्रियों से दूर रहना। भिक्षुओं के रास्ते में एक छोटी-सी नदी आई, जिसे पार कर दूसरी ओर जाना था। वहां किनारे पर एक युवती खड़ी थी, जिसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। उसने इन भिक्षुओं से कहा कि उसे पानी से डर लगता है और उनसे नदी पार करवाने का अनुरोध किया। उनमें से एक बौद्ध भिक्षु ने मानवता बोध के नाते उसे कंधे पर उठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। उसके साथी को यह कार्य बेहद अटपटा लगा। साथ ही वह इस घटना के बाद बेहद तनाव में आ गया। काफी देर बेचैन रहने के बाद उसने कहा- 'हमारे गुरुजी ने हमें स्त्रियों से दूर रहने को कहा था, लेकिन आपने तो उस स्त्री को कंधे पर बिठा लिया।' इस पर पहले भिक्षु ने मुस्कराते हुए कहा- 'मैंने तो उस युवती को कंधे से उतार कर अलग कर दिया है और तुम अभी भी उसका बोझ अपने दिलो-दिमाग में रखे हुए हो। उस समय उस युवती को मेरी मदद की आवश्यकता थी, मैंने मदद की और बात खत्म हो गई।' यह बात सुन कर दूसरे भिक्षु को अपनी भूल समझ में आ गई।

दुनिया मेरे आगे

हम सब अपने जीवन में अक्सर ऐसी भूल करते हैं। कितनी ही निरर्थक चीजों से दिमाग को भरे रहते हैं। हमारे साथ किसने गलत व्यवहार किया, किसने ढंग से बात नहीं की, सहायता नहीं की जैसी कई तरह की बातों के कड़वे या मीठे अनुभवों से हमने अपने दिमाग को बीमार करके रखा हुआ है। दरअसल, यह हमारी मानवीय समस्या है कि हम जिसे गलत मानते हैं, उसे देखते ही हमारे मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मन कसैला हो जाता है और दिन खराब हो जाता है। फिर भी हम उसे भूलते नहीं, जिससे हम खुद को परेशान करते रहते हैं। आए दिन ऐसी घटनाओं का सामना हम सभी को घर, ऑफिस, बाजार में या दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर होता रहता है। इससे हमारा दिमाग ऐसी घटनाओं का कूड़ाघर बनता चला जाता है। ऐसे में अगर हम अपने दिमाग पर इतना बोझ लादेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बड़े कैसे होंगे? यह सोचने की बात है कि अगर गाड़ी में जरूरत से ज्यादा सवारियां हो तो गाड़ी के साथ-साथ सवारियों की हालत कैसी हो जाती है। ऐसे में अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें हर दिन फालतू के इस दिमागी बोझ को उतारते चलना है। जब भी हम शाम में दफ्तर से निकलें तो उस दिन के सभी गिले-शिकवे या मतभेदों को वहीं छोड़ दें। अगर किसी से विवाद या मनमुटाव हो भी जाए तो सामने वाले से तुरंत कह देना चाहिए कि आज जो भी हमारे बीच हुआ, उसमें मेरी जो गलती थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उसकी गलती पर वह माफी मांगता है या नहीं, यह उसके सोचने का तरीका है। कम से कम आप अपना बोझ उतारें और आगे बढ़ जाएं। अगर आपसी रिश्तों में भी लड़ाई हो जाए तो उस विवाद को अगले दिन तक मत जाने दें। तुरंत सुलह करके खत्म कर दें। यह तथ्य है कि विकार और विवाद जितना लंबा खिंचेगा, उतनी ही समस्या उत्पन्न करेगा।

हालांकि यह सब करना आसान काम नहीं है, फिर भी कोशिश की जाए तो इसकी खुशी सबसे पहले हमें मिलेगी। कहावत है कि जो छोटी-छोटी बातों का जितना बोझ अपने दिमाग में रखेगा, वह उतना ही ज्यादा समस्याग्रस्त होगा। सफल वही बन सकता है जो भीतर से खुश और संतुष्ट हो। किसी पात्र में अगर पहले से बहुत सारी चीजें भरी हों तो उसमें अमृत के लिए भी जगह नहीं बन सकती। जिंदगी में वाकई कुछ बनना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है दिमाग में फालतू के बोझ लेना बंद कर देना चाहिए। दिमाग हमारा है, शरीर हमारा है, इसलिए उसकी खुशी के लिए हमें ही प्रयास करने होंगे। इसलिए दिमाग को इन फालतू की चीजों से दूर रखना चाहिए और सभी से संवाद बनाए रखने का प्रयास हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। छोटी-छोटी बातों को दिल पर लगा कर रखने से अच्छा है कि दिमाग को स्वतंत्र रखा जाए। अगर किसी को बोलने में दिक्कत है तो तो एसएमएस या सोशल चैट का इस्तेमाल कर गलतफहमियों को दूर कर लेने की जरूरत है। छोटी-छोटी गलतफहमियां हमारे जीवन को बाधित कर सकती हैं। इसलिए जीवन को नया आगाज देने के लिए यह जरूरी है कि हम इनसे दूर रहें। यह एक मशहूर पंक्ति है- 'जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दादिल क्या खाक जिएंगे।'

अपराध और दंड

राजस्थान के अलवर में हुए सामूहिक बलात्कार से दिल दहल उठा है। यह शर्मनाक वारदात राजनीति करने या चुनावी लाभ लेने का विषय नहीं बल्कि ऐसा माहौल बनाने का है कि भविष्य में सभ्य समाज को विचलित करने वाली ऐसी जघन्य घटनाओं पर लगाम लग सके। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने ही इस मामले को दबाने की कोशिश की ताकि उसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़े। एफआइआर दर्ज कराने में भी बहुत विलंब किया। काफी मशक्कत करने के बाद किसी तरह एफआइआर दर्ज हुई तो अपराधियों को पकड़ने में मुस्तैदी और सख्ती नहीं बरती गई। महज इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि लापरवाही और संवेदनहीनता का परिचय देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई क्योंकि यही अधिक जान पड़ता है कि जन आक्रोश को शांत करने के इरादे से यह कार्रवाई की गई।

इस मामले में तो ऐसी कार्रवाई की जरूरत थी जिससे कोई मिसाल कायम होती ताकि दुबारा ऐसी घटनाएं न हों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यह पुलिस के टालमटोल वाले रवैये का ही दुष्परिणाम रहा कि एक दलित महिला का उसके पति के सामने दुष्कर्म करने वालों ने अपने दुष्कृत्य का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस चाहती तो ऐसी होने से रोक सकती थी लेकिन वह चुनावों की चिंता कर रही थी। उसके नाकारापन की हद यह भी है कि वारदात के करीब एक सप्ताह बाद केवल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी।

अगर यही सब होता रहा तो समाज में महिलाओं के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं रहेगा। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए अनेक नियम-कानून बनाए गए हैं मगर उनका सही ढंग से पालन नहीं हो रहा। घर हो या बाहर, अक्सर महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं। उनके साथ घरेलू हिंसा तो आम बात है, दुष्कर्म और हत्या जैसी वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं।

● *दीपिका शर्मा, सूरजकुंड, गोरखपुर*

शिक्षा की उपेक्षा

देश में सरकारी स्कूल का बंद होना और निजी स्कूलों का तेजी से खुलना शुभ संकेत नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारे बिना देश का सतत विकास नहीं हो सकता। इनकी अनदेखी कर हम केवल एकतरफा विकास को बढ़ावा देते रहे हैं। अगर अब ध्यान नहीं दिया तो देर हो जाएगी। देश में शिक्षा का अधिकार कानून और सर्वशिक्षा अभियान जैसी योजनाएं लागू होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा की सेहत सुधर नहीं रही है। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस बाबत कोई बड़ा कदम उठाए।

राज्य सरकारें आज भी शिक्षा को लेकर पर्याप्त गंभीर नहीं हैं। शायद इसलिए कि यह उनके वोट बैंक को प्रभावित नहीं करती। दरअसल, समाज के कमजोर तबके के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जबकि संपन्न वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की उपेक्षा का आलम यह है कि उनमें शिक्षकों की नियुक्ति तक नहीं होती। इसके अलावा उन स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं ठीक करने पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं हो सकता है। असल बात दृढ़ इच्छाशक्ति की है। दिल्ली सरकार ने हाल में अपने स्कूलों पर अतिरिक्त ध्यान दिया और शानदार नतीजे आए हैं।

हम देश में 'नालेज पावर' तो बनाना चाहते हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधार पा रहे हैं। देश में प्राथमिक शिक्षा का हाल यह है कि आज भी पांचवीं कक्षा के करीब आधे बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ तक ठीक से नहीं पढ़ सके। इसलिए जरूरी है कि सरकार बुनियादी ढांचे के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे।

● *शादाब हुसैन खान, मांझी, छपरा, बिहार*

यह नजीर

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक दंपति पर तीन पेड़ काटने पर चार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये पेड़ घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काटे गए थे। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर इतनी सख्त सजा तारीफ के काबिल है। पर्यावरण की रक्षा करनी है तो नुकसान पहुंचाने वाले को कड़े से कड़े जुर्माने व सजा से दंडित किया जाना ही चाहिए। इसके विपरीत हमारे देश में सरे आम वृक्षों को काटा जा रहा है, वन्य जीव-जंतुओं का शिकार किया जा रहा है, फिर भी बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटे जाने या अवैध शिकार के समाचार सुनने-पढ़ने को नहीं मिलते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र व प्रदेशों की सरकारों को भी कड़ाई से पेश आना होगा, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों में भय पैदा हो। पर्यावरण की रक्षा महज भाषणों और गोष्ठियों से नहीं होती है, यह बात हमें समझनी होगी।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

समुद्री प्रदूषण

हाल ही में किए एक शोध के अनुसार दुनिया में हर साल करीब तीस करोड़ टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से अधिकांश नदियों द्वारा बहा कर लाया जाता है। सिर्फ दुनिया की दस नदियां मिल कर करीब नब्बे फीसद कचरा समुद्र में मिला देती हैं। भारत की गंगा के साथ ही अन्य बड़ी नदियां लाखों टन कूड़ा-कचरा और अवशिष्ट पदार्थ समुद्र में मिला देती हैं। हालत यह है कि इन पतित पावन नदियों का पानी पीने लायक तो क्या, आचमन लायक भी नहीं रहा। पॉलिथीन के बढ़ते प्रयोग और नदियों के किनारे बढ़ती मानव बस्तियों और कल-कारखानों से निकले अवशिष्ट पदार्थों ने इन नदियों को गंदे नाले में बदल दिया है। अब तो समुद्र के जीव-जंतु भी इस प्रदूषण के शिकार होकर मर रहे हैं।

हाल ही में अमेरिकी खोजकर्ता विक्टर वेस्कोवो दुनिया में पहली बार समुद्र की गहराई में ग्यारह किलोमीटर अंदर तक गए तो उन्हें वहां भी प्लास्टिक का कचरा मिला। प्रशांत महासागर का मारिया ट्रेंच, जो दुनिया में सबसे गहरा समुद्री स्थान कहलाता है, आज कूड़े-कचरे से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया भर के महासागरों में करीब दस करोड़ टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो चुका है और यह बढ़ता ही जा रहा है। इससे हर हाल में शीघ्र ही निजात पाने की जरूरत है।

● *संजय डागा, हातोद, इंदौर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com